Constitution Leading Case Law

(1) जीविकोपार्जन का अधिकार - ओलगा टेलिस बनाम बाम्बे म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, ए० आई० आर० 1986 एस० सी० 180

(2) शिक्षा का अधिकार - उन्नीकृष्णन बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, (1993) 4 SCC 645 अनु० 41 और अनु० 21 की भावना के अनुरूप अनु. 45 को मूलाधिकार घोषित किया गया। 42वें संशोधन अधिनियम, 2001 के द्वारा अनु० 21A अन्तः स्थापित करके 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क शिक्षा, राज्य द्वारा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। शून्य से 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा का दायित्व उनके अविभावकों पर डाल दिया गया है इसके लिए अनु. 51 के खण्ड क (नीति निदेशक तत्व) में उपबन्ध किया गया है।

(3) चिकित्सा का अधिकार - परमानन्द कटारा बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 1989 एस० सी० .

(4) एकान्तता का अधिकार – गोविन्द बनाम मध्य प्रदेश राज्य ए० आई० आर० 1975 एस० सी० 1379) " राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य 1994 (S.C.)

LawSpark Institute

(5) विदेश भ्रमण का अधिकार - सतवन्त सिंह साहनी बनाम डी. रामबलम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली ए० आई० आर० 1967 एस० सी० 1836। इसका मेनका गाँधी ए० आई० आर० 1978 वाद में समर्थन किया गया ।

(6) विधिक सहायता का अधिकार - एम०एच० हास्काट बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1978 SC 1548

(7) शीघ्र विचारण का अधिकार - चम्पालाल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1981 (S.C.)

(8) आत्महत्या करने का अधिकार-

(क) मूलाधिकार है- पी० रथीनम बनाम भारत संघ, 1994।

(ख) मूलाधिकार नहीं है – महाराष्ट्र राज्य बनाम मारूति श्रीपति, ए. डुबल 1996S.C

जीने के अधिकार से मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं — ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, ए० आई० आर० 1996 एस० सी० 946

Lawspark Institute

(9) आहार का अधिकार – पी०यू०सी० एल० बनाम भारत संघ, 2000 (5) एस० सी० सी० 30

(10) मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार - मेनका गाँधी बनाम भारत संघ, ए० आई० आर० 1978 एस० सी० 507

(11) आश्रय का अधिकार – चमेली सिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य

(12) शीघ्रतर परीक्षण का अधिकार – हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य, AIR 1979 SC 1360

(13) श्रमजीवी महिला का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार – विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, AIR 1997 SC 3011

(14) प्रत्येक व्यक्ति को अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है— जोगिन्दर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1994 SCC 260

(15) हथकड़ी लगाने (Hand cuffing) विरुद्ध संरक्षण- प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन, AIR 1980 SC 898

Lawspark Institute

(16) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण- नीलवती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य, (1993) 2 SCC746

(17) राज्य सरकार द्वारा अवैध निरोध किये जाने पर निरुद्ध व्यक्ति को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार- रूदल शाह बनाम बिहार राज्य, (1983) 4 SCC

(18) प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के उपभोग का अधिकार – सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, AIR 1991 SC 420

(19) शोर प्रदूषण के विरुद्ध निजात पाने का अधिकार– 1. इन री शोर प्रदूषण (लाऊड स्पीकर नियंत्रण), (2005) 5 SCC 733

2. डॉ. बलवन्त सिंह बनाम पुलिस आयुक्त, JT 2014 (12) SC 477

(20) विकलांग तथा अंधे व्यक्ति को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में प्रतियोगी के रूप में भाग लेने का अधिकार है— नेशनल फेडरेशन आफ ब्लाइण्ड बनाम संघ लोक सेवा आयोग, (1993) 4 SCC

(21) न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार - पीपुल्स यूनियन फार डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ, AIR 1981 SC 1473

Lawspark Institute

(20) मस्जिदों के इमामों को पारिश्रामिक पाने का अधिकार है— आल इण्डिया इमाम संगठन बनाम भारत संघ, (1993) 3 SC 584

(21) सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान का निषेध - मुरली एस० देवड़ा बनाम भारत संघ, AIR 2002 SC 4

(22) कारागार में सजा भुगत रही महिला के साथ रहने वाले बच्चों के हितों का संरक्षण - आर०डी० उपाध्याय बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य, AIR 2006 SC

(23) परम्परागत धरोहर को बनाए रखना अनु० 21 और नीति निदेशक तत्व के अनु0 51 क (9) के अन्तर्गत राज्य का कर्तव्य है – सुशान्ता टैगोर बनाम भारत संघ, AIR 2005 SC 1975

(24) कौमार्य परीक्षण अनु० 21 के अन्तर्गत प्राप्त एकान्तता के अधिकार का अतिलंघन है— सुरजीत

सिंह थिंड बनाम जीत कौर, AIR 2003 पंजाब एण्ड हरियाणा 353

(25) चरित्रहीन महिला को भी एकान्तता का अधिकार प्राप्त है – महाराष्ट्र राज्य बनाम मधुलकर नारायण, - AIR 1991 SC 2007

Lawspark Institute

(26) प्राप्तवय (Mazority) बालिका को स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार है - लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 2006 SC 2522

(27) बलात्कार पीड़ित महिला को अंतरिम प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार है- बोधसत्व गौतम बनाम शुभ्रा चक्रवर्ती, (1996) 1 SC 490

(28) पैतृकता निर्धारण के लिए रक्त परीक्षण न कराने का अधिकार – निगंमार बनाम चिकैय्या, AIR 2000 कर्नाटक 50

(29) अनुच्छेद 21 का संरक्षण विदेशियों को भी प्राप्त है— राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य, (1999) 1 SCC 742

(30) अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक न होने पर भी अग्रिम जमानत से इन्कार अनु॰ 21 का अतिलंघन है— जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, AIR 2012 SC 1676

(31) एकान्तता का अधिकार आत्यन्तिक अधिकार नहीं है। इस पर युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाया जा सकता है—मि॰ एक्स बनाम हास्पिटल जेड, AIR 1999 SC 445

Lawspark Institute

(33) टेलीफोन टेप करना व्यक्ति के एकान्तता के अधिकार में हस्तक्षेप है, यह अपरिहार्य परिस्थितियों में ही अनुज्ञात किया जा सकता है – पीपुल्स यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन आफ इण्डिया, AIR 1997 SC 568

(34) बिजली पाने का अधिकार अनु० 21 के अन्तर्गत आता है— एम० के० आचार्य बनाम भारत संघ, AIR 2008 कोलकत्ता 47

(35) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 303, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है अतः असंवैधानिक हैमिट्टू सिंह बनाम पंजाब

(36) राज्य, AIR 1983 SC 473 (36) गर्भधारण के पूर्व लिंग परीक्षण न कराने का अधिकार - विजय शर्मा बनाम भारत संघ, AIR 2008

(37) नार्को, ब्रेन मैपिंग तथा पॉलीग्राफी टेस्ट न कराने का अधिकार - सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य, AIR 2010 SC 1974

(38) एक महिला को बच्चा पैदा करने या न करने के विकल्प का अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रत्याभूत दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार

Lawspark Institute

सम्मिलित है— सुचेता श्रीवास्तव बनाम चण्डीगढ़ प्रशासन, AIR 2010 SC 235

(39) पक्षकारों के दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन का उपबन्ध करने वाली हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है— सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा, (1984) 4 SCC

(40) "मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार" प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है और इसे सुरक्षित करने के लिए आवश्यक सुविधायें प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य है – विक्रमदेव सिंह तोमर बनाम बिहार राज्य, AIR 1988 SC 1782

(41) निष्पक्ष विचारण का अधिकार विधि की सम्यक् प्रक्रिया में निहित है— रत्तीराम बनाम म०प्र० राज्य, AIR 2012 SC 1485

(42) अभियोजन आरम्भ होने से कई वर्षों को समाप्ति ही

अभियोजन को रोक देने या परिवाद वापस लेने को औचित्यपूर्ण नहीं बनाती है— मोहम्मद हुसैन उर्फ जुल्फिकार अली बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) दिल्ली, AIR 2012 SC 3860

Lawspark Institute

(43) फुटपाथों पर व्यापार करना मूल अधिकार- हैसोदन सिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी, ए० आई० आर० 1989 एस० सी० ।

(44) अभियुक्त को अकारण जमानत पर न छोड़ना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है – बाबू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, AIR 1978 SC 527

ए० के० गोपालन बनाम मद्रास राज्य, ए० आई०

Lawspark Institute